एम.टी. एनरिका लेक्सी और अन्य ।

बनाम

दोरम्मा और अन्य ।

(सिविल अपील संख्या 4167 /2012)

2 मई 2012

[आर.एम. लोढ़ा और एच.एल. गोखले, जे.जे.]

अन्वेषण और जब्ती:

कुछ संपत्ति जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति - दो इतालवी जहाज़ से गोलीबारी के परिणामस्वरूप भारतीय मछुआरों की मौत हो गई। - केरल पुलिस द्वारा जहाज के मास्टर को जारी किया गया पत्र,पूर्व अनुमति के बिना अपनी यात्रा जारी नहीं रखने के लिए अवधारित माना जाता है कि जहाज का अपराध का उद्देश्य नहीं था। जांच के दौरान जो भी परिस्थितियां सामने आयी उससे जहाज द्वारा किसी अपराध के घटित होने का संदेह उत्तपन होना - आगे कहा गया है कि जहाज को जो कब्जे में लिया गया है इस मामले में सुरक्षा उपायों की इतनी आवश्यकता नहीं थी, अद्धिकांषतः सभी सुरक्षा उपाय जहाज और उसके मालिकों द्वारा देखभाल की गई। - इटली गणराज्य

द्वारा दिया गया आश्वासन-यदि आवश्यक हो तो चार नौ सैनिकों की उपस्थिति -न्यायालय या वैध प्राधिकारी के समक्ष सुनिश्चित पूरी तरह से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है और राज्य सरकार के हितों की पूर्णतः रक्षा करता है- यह किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के अधिकार को, राज्य जांच करें और अपराधियों पर मुकदमा चलाएं। -सरकार और उसके अधिकारी जहाज को अपनी यात्रा शुरू करने कि अनुमति निर्णय में दिए निर्देशों के अधीन देंगे। - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 102।

दिनांक 15.2.2012 को एक भारतीय नाव के मालिक द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि एक इटालियन जहाज (अपील कर्ता १) के अंधाधुंध गोलीबारी का परिणाम स्वरुप इसके दो मछुआरे की मृत्यु हो गई. जांच के दौरान केरल पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर ने एक पत्र जारी किया कि अपीलकर्ता के मास्टर नं. 1 जहाज उसकी पूर्व अनुमति के बिना अपनी यात्रा जारी नहीं रखेगा। जहाज और उसके मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका स्टैंड यह था कि जहाज का मास्टर किसी भी तरह से नहीं था इस गोलाबारी का जिम्मेदार नहीं था और सेना के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता

था। एनएमपी दस्ते द्वारा की गई गतिविधियाँ जो थीं सीधे इटली गणतंत्र की सेना की कमान के तहत रहती है। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जहाज को कुछ शर्तों के अधीन यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी। मृत मछुआरे में से एक की पत्नी द्वारा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की। डिवीज़न बेंच सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करके जहाज और उसके मालिक को सक्षम क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 457 के तहत आवेदन करने के दिशानिर्देश प्रदान किये। व्यथित, जहाज और उसके मालिक ने अपील दायर की.

इस बीच तीन नौ वाहन विभाग, मछली पकड़ने वाली नाव का मालिक और मृतक मछुआरे के वारिस द्वारा मुकदमे दायर किये गए। लोक अदालत से पहले तीन समझौते हुए। राज्य सरकार ने दलील दी कि उक्त समझौते लोक नीति के साथ-साथ भारतीय नीति के भी विरुद्ध थीं और कानूनी तौर पर उचित तरीके से चुनौती दी जाएगी। इटली गणराज्य को भी हस्तक्षेप की अनुमति दी गई।

कोर्ट ने अपील को अभिनिर्धारित किया

1. प्रक्रिया में पुलिस अधिकारी जांच सीआरपीसी की धारा 102 के तहत ऐसी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकती है जो संपत्ति चोरी होने का आरोप है या होने का संदेह है, चोरी की गई या जांच के तहत अपराध की वस्तु है या जिसका अपराध घटित होने से सीधा संबंध है।

पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी को संपत्ति को जांच में जब्त नहीं किया जा सकता जिसका अपराध के घटित होने का संदेह नहीं हो। संहिता की धारा 102 के अनुसार पुलिस अधिकारी वह संपत्ति जो धारा 102(1) के अंतर्गत आती है जब्त कर सकता है और कोई अन्य नहीं। (पैरा13] (181-जी-एच; 182-ए]

1.2. यह स्वीकृत मामला है कि जहाज का जुर्म का धेय नहीं थाऔर ही कोई ऐसी परिस्थिति सामने आई है कि जहाज के द्वारा अपराध नहीं किया गया था। अतः जहाज का निरोध कि जरूरत नहीं थी। तत्संबंधी दृष्टि से आदेश हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के के आदेश जिसके तहत एकल न्यायाधीश का आदेश को निरस्त किया गया, अपास्त किया गया। [पैरा 14] [182-सी-डी]

1.3. दो बातें स्पष्ट करना आवश्यक है - (i) में

इस तत्काल अपील में न्यायालय सीधे तौर पर समझौते की शुद्धता, वैधता या वैधता के साथ इटली गणराज्य और दावेदारों के बीच समझौता हुआ चिंतित नहीं है अपितु कुछ खंडों को ध्यान में रखते हुए इस अपील के निपटारे हेतु, समझौते नज़रअंदाज़ करने लायक हैं; और

(ii) इस अपील में इस न्यायालय के लिए आवश्यक स्थिति पर विचार करना आवश्यक है तो वह यह है की जहाज को यात्रा की अनुमति दे जाये या नहीं, न कि इटली गणराजय द्वारा आक्षेपित भारतीय प्राधिकारियों और न्यायालयों का क्षेत्राधिकार के संबंध में । [पैरा 23] [186-ई-एच; 187-ए]

1.4. जहाज़ और उसके मालिक द्वारा अधिकांश सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। हालाँकि, इटली गणराजय के लिए चार नामित नौसैनिकों की उपस्थिति को सुरक्षित कर रहा है। स्पष्ट रूप से कहा गया कि इटली गणराज्य सहमत है कि यदि 4 मरीन की उपस्थिति की आवश्यकता किसी भी अदालत को या किसी न्यायालय या वैध प्राधिकारी द्वारा जारी समन,करे तो इटली गणराज्य, उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। ये आश्वासन, बुलाए गए व्यक्तियों के अधिकार के अधीन रहेगा और इसे भारत में सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दे

सकेंगे। इटली गणराज्य द्वारा दिया गया आश्वासन न्याय का उद्देश्य और पूरी तरह से लोगों के हितों की रक्षा करना और राज्य सरकार और किसी भी तरह से जांच को आगे बढ़ाने और मुकदमा चलाने के उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। [पैरा 24, 25] [187 -बी-एफ]

1.5. राज्य सरकार और उसके प्राधिकारी जहाज को अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति इस निर्णय में दिए गए निर्देशो के तहत देंगे। [पैरा 26] [187-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 4167/2012.

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.04.2012 के डब्ल्यू ए नंबर 679/2012 से।

गुलाम ई. वाहनवती, अटॉर्नी जनरल, इंदिरा जयसिंह, एएसजी, के.के. वेणुगोपाल, वी.जे. मैथ्यू, गोपाल सुब्रमण्यम, हरीश एन. साल्वे, सुहैल दत्त, राघेंथ बसंत, विपीन वर्गीस, अंकुर तलवार, अर्जुन सिंह भाटी (सेंथिल जगदीसन के लिए), हैरिस बीरन, निशांत पाटिल, प्रशांत पाटिल, सुप्रिया जैन, रेखा पांडे, डी.एस. माहरा, एम.टी. जॉर्ज, के.टी. कविता, पी.वी. दिनेश, पी.वी. विनोद, जैमन एंड्रयूज, पी.पी. संधू, रॉबिन वी.एस. परमेश्वरन नायर, दलजीत टाइटस, अभिक्षित सिंह,

अचिंत सिंह ज्ञानी, जगजीत सिंह छाबड़ा, जसवन्त पेर्राया, अंकुर मनचंदा उपस्थित पक्षों के लिए ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

आर.एम. लोढ़ा, जे.

1. अपील सुनवाई हेतु स्वीकार की गई।

2. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केके वेणुगोपाल, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री गुलाम ई. वाहनवती और प्रतिवादी संख्या 2 & 3 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम को सुना ।तामील के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 1 अनुपस्थित ।

3. जहाज -एमटी एनरिका लेक्सी - और मेसर्स डॉल्फिन टैंकर एसआरएल (जहाज का मालिक) 3 अप्रैल, 2012 को केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपील में हैं, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश का निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 मार्च २०१२ को रद्द कर दिया था।

4. विवाद इस प्रकार है कि- 15 फरवरी, 2012 को भारतीय पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नाव सेंट एंटनी के मालिक फ्रेडी द्वारा

नींदकारा तटीय पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि उस दिन शाम 4.30 बजे (आईएसटी) जब मछली पकड़ने वाली नाव सेंट एंटनी अरब सागर से गुजर रही थी, एक इतालवी जहाज -एमटी एनरिका लेक्सी (प्रथम अपीलकर्ता) द्वारा आपत्तिजनक गोलीबारी की गई थी। पहले अपीलकर्ता जहाज से गोलीबारी के परिणामस्वरूप, मछली पकड़ने वाली नाव सेंट एंटनी पर सवार दो निर्दोष मछुआरों की मृत्यु हो गई और नाव पर सवार अन्य लोगों ने अपनी जान बचाई क्योंकि वे नाव के डेक पर लेटे हुए थे। एफआईआर के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत अपराध संख्या 2/2012 दर्ज किया गया था। नींदकारा तटीय पुलिस स्टेशन ने मामले की जानकारी तटरक्षकों को भी दी और तदनुसार, पहले अपीलकर्ता जहाज को रोक लिया गया और 16 फरवरी, 2012 को कोचीन बंदरगाह पर लाया गया। कथित तौर पर अपराध करने वाले दो नौसैनिकों को 19 फरवरी, 2012 को गिरफ्तार किया गया था।

5. उपरोक्त अपराध की जांच के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि 26 फरवरी, 2012 को, संबंधित सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर ने पहले अपीलकर्ता जहाज के मास्टर को एक

पत्र जारी किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि जहाज उनकी पूर्व मंजूरी के बिना अपनी यात्रा जारी नहीं रखेगा।

6. प्रथम अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि वह 24 चालक दल के सदस्यों के साथ सिंगापुर से मिस्र जा रही थी। जहाज पर छह नौसैनिक कर्मी यानी नौसेना सैन्य सुरक्षा दस्ता (एनएमपी दस्ता) भी सवार थे। अरब सागर में सोमालियाई समुद्री डाकुओं के गंभीर खतरे के कारण एनएमपी दस्ते को इटली गणराज्य की सरकार द्वारा पहले अपीलकर्ता जहाज पर तैनात किया गया था। दूसरा अपीलकर्ता - जहाज का मालिक -इतालवी जहाज मालिक परिसंघ का सदस्य है। रक्षा मंत्रालय -नौसेना स्टाफ और इतालवी जहाज मालिक परिसंघ के बीच समझौते के अनुसार समुद्री डकैती और सशस्त्र लूटपाट के कारण जहाज को कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएमपी दस्ता जहाज पर था। समुद्री डकैती के हमलों, यदि कोई हो, का मुकाबला करने में शामिल संचालन से संबंधित विकल्पों के लिए जहाज का मास्टर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है; जहाज का मालिक समुद्री डाकुओं के हमलों की स्थिति में जहाज, उसके चालक दल और माल की रक्षा के लिए एनएमपी दस्ते द्वारा की जाने वाली सैन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और जहाज पर मौजूद

एनएमपी दस्ता हमेशा इटली गणराज्य के सेना की सीधी कमान के अधीन होता है।

7. अपीलकर्ताओं के अनुसार, हालांकि सभी एजेंसियों ने अपनी-अपनी जांच पूरी कर ली थी, लेकिन उनमें से कोई भी जहाज को रवाना करने के लिए आधिकारिक मंजूरी नहीं दे रहा था और नौकायन और अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ने के लिए अपीलकर्ता जहाज, उचित निर्देश और अनुमति के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए अग्रसर हुए।

8.रिट याचिका के जवाब में सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया. एकल न्यायाधीश ने, पक्षों को सुनने के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, और वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया कि वे पहले अपीलकर्ता जहाज को कुछ शर्तों पर अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति दें।

9. 29 मार्च 2012 के एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर, दोरम्मा (मृत मछुआरों में से एक की पत्नी) ने, अन्य बातों के अलावा, रिट अपील संख्या 679 /2012 दायर की। केरल उच्च की डिवीजन बेंच अदालत ने कहा कि मामले में जांच

अभी तक पूरी नहीं हुई है और कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है और अब चूंकि जांच अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'संहिता') की धारा 102 (3) के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है), इस मामले पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 457 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचार करने की आवश्यकता थी और एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को अनुमति देना और निर्देश जारी करना उचित नहीं था। तदनुसार, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को संहिता की धारा 457 के तहत एक आवेदन के साथ क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की अनुमति दी और कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के बाद प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का विवेकपूर्ण निपटान करना चाहिए।

10. इस न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, कुछ घटनाओं ने हस्तक्षेप किया है। तीन एडमिरल्टी मुकदमों में - एक वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 -डोरम्मा द्वारा दायर किया गया, दूसरा पहले इत्तला कर्ता फ्रेडी द्वारा, और तीसरा अभिनय जेवियर और अगुना जेवियर द्वारा दायर किया गया, इनमें से कार्यवाही के पक्षकार के रूप में इटली गणराज्य को सम्मिलत करने के बाद समझौते हुए हैं। ।

वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 -दोरम्मा के साथ समझौता और अभिनय जेवियर और अगुना जेवियर के साथ समझौता 24 अप्रैल, 2012 को हुआ, जबकि फ्रेडी के साथ समझौता 27 अप्रैल, 2012 को हुआ। तीनों समझौते लोक अदालत से पहले हुए। केरल सरकार इन तीन समझौतों की विभिन्न शर्तों से गंभीर रूप से व्यथित है। केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने पुरजोर तर्क दिया कि ये समझौते सार्वजनिक नीति और भारतीय कानूनों के खिलाफ थे। उन्होंने तर्क दिए कि केरल सरकार इन समझौतों को उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही में चुनौती देने का इरादा रखती है।

11. इस अपील की सुनवाई के दौरान, इटली गणराज्य की ओर से हस्तक्षेप के लिए एक मौखिक आवेदन किया गया था। हमने इटली गणराज्य के हस्तक्षेप की अनुमति दी, विशेष रूप से अपील में दिए गए बयानों के मद्देनजर कि एनएमपी दस्ते में छह इतालवी नौसेना कर्मी शामिल थे जो हमेशा इटली गणराज्य की सीधी कमान के अधीन थे और जहाज पर नौसेना कर्मियों द्वारा की जाने वाली सैन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इटली गणराज्य द्वारा हस्तक्षेप भी हमें उचित लगा क्योंकि इटली गणराज्य और तीन

एडमिरल्टी सूट में दावेदारों-वादी के बीच हुए तीन समझौतों को केरल सरकार द्वारा गंभीर चुनौती दी गई थी।

12. इससे पहले कि हम मामले पर आगे विचार करें, हम संहिता की धारा 102 का संदर्भ ले सकते हैं जो इस प्रकार है:

"102. कुछ संपत्ति जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.-

(1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में आरोप लगाया जा सकता है या चोरी होने का संदेह हो सकता है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करता है।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि वह किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ है, तो जब्ती की रिपोर्ट तुरंत उस अधिकारी को देगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की रिपोर्ट करेगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि इसे आसानी से अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है या जहां उचित आवास सुरक्षित करने में कठिनाई हो रही है ऐसी संपत्ति की हिरासत, या जहां संपत्ति को पुलिस हिरासत में रखना जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक

नहीं माना जा सकता है, वह किसी भी व्यक्ति को अदालत के समक्ष संपत्ति का उत्पादन करने के लिए बांड निष्पादित करने पर उसकी हिरासत दे सकता है। और जब आवश्यक हो और उसके निपटान के संबंध में न्यायालय के अगले आदेशों को प्रभावी करना:

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत जब्त की गई संपत्ति त्वरित और प्राकृतिक क्षय के अधीन है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपये से कम है, तो यह हो सकता है पुलिस अधीक्षक के आदेश के तहत तुरंत नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और धारा 457 और 458 के प्रावधान, जहां तक संभव हो सके, ऐसी बिक्री की शुद्ध आय पर लागू होंगे।"

13. जांच के दौरान पुलिस अधिकारी धारा 102 के तहत किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है यदि ऐसी संपत्ति चोरी होने का आरोप है या चोरी होने का संदेह है या जांच के तहत अपराध का उद्देश्य है या अपराध के कमीशन के साथ सीधा संबंध है जिसके लिए पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं. जिस संपत्ति की पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही हो, जिस पर अपराध होने का संदेह न हो, उसे जब्त नहीं किया जा सकता। संहिता की धारा 102 के तहत ,पुलिस

अधिकारी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जो धारा 102(1) के अंतर्गत आती है और किसी अन्य के अंतर्गत नहीं।

14. केरल उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद, 26 मार्च, 2012 को लंबित रहने के दौरान ,सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोल्लम के समक्ष संहिता की धारा 102 की उप-धारा (3) के तहत एक रिपोर्ट दायर की गई थी ने उस अदालत को रिपोर्ट दी कि पहला अपीलकर्ता जहाज जब्त कर लिया गया है। केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम से हमारे विशिष्ट प्रश्न के लिए, क्या पहला अपीलकर्ता जहाज अपराध का उद्देश्य था या जांच के दौरान ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई हैं जो किसी भी अपराध के कमीशन का संदेह पैदा करती हैं। प्रथम अपीलकर्ता पोत, श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने नकारात्मक उत्तर दिया। केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि इस मामले में अब पहले अपीलकर्ता जहाज को कब्जे में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके मद्देनजर, एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए डिवीजन बेंच के आदेश को जाना होगा और हम तदनुसार आदेश देंगे। 15. अब प्रश्न यह है कि क्या 29 मार्च 2012 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित

आदेश को जस का तस रहने दिया जा सकता है या संशोधित किये जाने योग्य है।

16. विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री गुलाम ई. वाहनवती ने शुरुआत में कहा कि भारत संघ का वही स्थान है जो केरल सरकार का है। उन्होंने भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अवर सचिव पी. शशि कुमार द्वारा भारत संघ की ओर से दायर संक्षिप्त जवाबी हलफनामे का हवाला दिया। उक्त जवाबी हलफनामे के पैरा 6 में कहा गया है कि प्रथम अपीलकर्ता जहाज के संबंध में भौतिक साक्ष्य मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 358 और 359 के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक जांच के दौरान एकत्र किए गए हैं। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केरल राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

17. केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने पहले ही संकेत दिया था कि पहले अपीलकर्ता जहाज को रोकने की अब आवश्यकता नहीं है। यदि प्रथम अपीलकर्ता जहाज को अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति दी गई तो उन्हें कोई गंभीर आपत्ति नहीं थी। हालाँकि, उन्होंने निम्नलिखित सुरक्षा उपायों की मांग की, अर्थात्, (i) अपीलकर्ताओं को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत

होना चाहिए और उन्हें इटली गणराज्य और इटली गणराज्य के बीच हुए एडमिरल्टी सूट में निपटान के बारे में अपनी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। दावेदार-वादी; (ii) छह क्रू सदस्यों, अर्थात् विटेली अम्बर्टो (मास्टर), नोविल्लो कार्लो (मास्टर एसएन), जेम्स मांडली सैमसन (मुख्य अधिकारी), साहिल गुप्ता (द्वितीय अधिकारी), फुलबेरिया (सीमैन) और तिरुमाला राव की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए (ऑर्डिनरी सी मैन) और चार मरीन, अर्थात्, वोग्लिनो रेनैटो (सार्जेंट), एंड्रोनिको मासिमो (प्रथम कॉर्पोरल), फोंटानो एंटोनियो (तीसरा कॉर्पोरल) और कोंटे एलेसेंड्रो (कॉर्पोरल), पहले अपीलकर्ता पोत के मास्टर द्वारा एक वचन पत्र दिया जाना चाहिए। , पहले अपीलकर्ता जहाज के मालिक के प्रबंध निदेशक और शिपिंग एजेंट के प्रबंध निदेशक, अर्थात्, जेम्स मैकिनटोश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड; और (iii) यह स्पष्ट किया जाए कि केरल सरकार के हित इटली गणराज्य और दावेदार-वादी के बीच हुए समझौतों से अप्रभावित रहेंगे और केरल सरकार इन समझौतों को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। .

18. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केके वेणुगोपाल ने केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा की

गई दलीलों के जवाब में कहा कि अपीलकर्ता इटली के और एडमिरल्टी सूट में दावेदार-वादी के बीच हुए समझौते से जुड़े नहीं थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पहले अपीलकर्ता जहाज पर चालक दल के छह सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, पहले अपीलकर्ता जहाज के मास्टर, पहले अपीलकर्ता जहाज के मालिक के प्रबंध निदेशक और जहाज के प्रबंध निदेशक द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। शिपिंग एजेंट, अर्थात्, जेम्स मैकिंतोश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने, वास्तव में, भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के प्रति समर्पण कर दिया है और वे उस स्थिति को बनाए रखते हैं। जहाज पर चार नौसैनिकों के संबंध में, श्री केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि नौसैनिक इटली गणराज्य की सेना की सीधी कमान के अधीन हैं, पहले अपीलकर्ता जहाज के मालिक या मास्टर कोई वचन देने या कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं थे।

19. चूंकि हमने इटली गणराज्य को मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है, इसलिए हम इटली गणराज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे से जानना चाहते थे कि क्या इटली गणराज्य इस न्यायालय को कोई आश्वासन देने की स्थिति में है। जांच

अधिकारी या किसी न्यायालय या वैध प्राधिकारी द्वारा जब भी आवश्यक हो, चार नौसैनिकों, वोग्लिनो रेनाटो (सार्जेंट), एंड्रोनिको मास्सिमो (प्रथम कॉर्पोरल), फोंटानो एंटोनियो (तीसरा कॉर्पोरल) और कोंटे एलेसेंड्रो (कॉर्पोरल) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए , श्री हरीश साल्वे ने हमें इटली गणराज्य की स्थिति दर्शाते हुए एक लिखित नोट सौंपा जो इस प्रकार है:-

"1. इटली गणराज्य की स्थिति यह है कि कथित घटना भारतीय क्षेत्रीय जल के बाहर हुई थी और भारत संघ और केरल राज्य के पास आपराधिक कानूनों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून सहित भारतीय नगरपालिका कानूनों के तहत मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कानून; यह घटना दो संप्रभु राज्यों, यानी, भारत गणराज्य और इटली गणराज्य के बीच है और यह विवाद समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून और सम्मेलनों द्वारा प्रदान किया जाता है।

2. इटली गणराज्य ने अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की और केरल उच्च न्यायालय में उचित कार्यवाही द्वारा केरल में शुरू की गई कानूनी कार्यवाही को भी चुनौती दी है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों [और दायित्वों] पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और इन दो याचिकाओं में उठाए गए संप्रभु प्रतिरक्षा के अपने तर्कों

सहित, और यह स्वीकार किए बिना कि भारत संघ या केरल राज्य की कार्रवाइयां कानून द्वारा अधिकृत हैं, गणतंत्र इटली भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन देने के लिए सहमत है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय या वैध प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी सम्मन के जवाब में इन नौसैनिकों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो इटली गणराज्य उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। भारत में सक्षम अदालत के समक्ष ऐसे समन/आदेश को चुनौती देने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के अधिकार के अधीन होगा।

3. इस आश्वासन पर यह माननीय न्यायालय, यदि उचित समझे, निम्नलिखित के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है:-

जहाज को भारत से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, और नौसैनिक जहाज पर [सभी उपकरणों, हथियारों और गोला-बारूद के साथ] सवार होंगे और भारतीय क्षेत्रीय जल को पार करेंगे।

4. इस आश्वासन को किसी भी तरह से इटली गणराज्य के रुख से अलग नहीं माना जाना चाहिए कि उसके अधिकारी संप्रभु प्रतिरक्षा के हकदार हैं और भारतीय नगरपालिका कानूनों के तहत भारत में कार्यवाही अवैध है।

5. यदि उचित कानूनी कार्यवाही में [इस माननीय न्यायालय में इटली गणराज्य द्वारा दायर याचिका सहित] यह घोषित किया जाता है कि भारत में कार्यवाही अवैध है, तो ये आश्वासन समाप्त हो जाएंगे।"

20. इटली गणराज्य द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान के जवाब में, विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री गुलाम ई. वाहनवती ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ उपरोक्त बयान में दिए गए आश्वासनों की सत्यता को स्वीकार नहीं करता है और, किसी भी मामले में , यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इटली गणराज्य द्वारा अपनाई गई स्थिति किसी भी तरह से इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या मंच में कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

21. केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने इटली गणराज्य के उपरोक्त बयान का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त बयान केरल सरकार को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अपराध की जांच करने और दो मछुआरों की मौत के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाने के केरल सरकार के अधिकार पर भी जोर दिया।

22. प्रासंगिक रूप से, इटली गणराज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने यह भी प्रस्तुत किया कि इटली गणराज्य और

दावेदारों-वादी के बीच हुए समझौते को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया जा सकता है। भारत का संविधान. श्री हरीश साल्वे ने आगे कहा कि निपटान के तहत भुगतान इटली गणराज्य द्वारा दावेदारों-वादी को उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में मुआवजे के रूप में नहीं बल्कि सद्भावना और इशारे के माध्यम से किया गया है।

23. हम दो बातें स्पष्ट कर सकते हैं -

(i) वर्तमान अपील में, हम इटली गणराज्य और दावेदारों-वादी के बीच हुए समझौतों की शुद्धता, वैधता या वैधता से सीधे तौर पर चिंतित नहीं हैं। समझौते में कुछ खंडों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, इन समझौते के खंडो को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं, और

(ii) इस अपील में विचार के लिए सीमित प्रश्न निम्नलिखित के संबंध में है पहले अपीलकर्ता जहाज की यात्रा और इसलिए, हमारे लिए इटली गणराज्य द्वारा अपनाई गई स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है कि कथित घटना क्षेत्रीय जल के बाहर हुई थी और भारत संघ और केरल राज्य के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। नगरपालिका कानूनों के तहत मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र और भारत संघ

और केरल राज्य द्वारा उस स्थिति का कड़ा खंडन और भारत संघ और केरल राज्य द्वारा मजबूत दावा कि दो भारतीय नागरिकों की हत्या का अपराध था भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

24. केरल सरकार के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा मांगे गए अधिकांश सुरक्षा उपायों का प्रथम अपीलकर्ता जहाज और उसके मालिक द्वारा ध्यान रखा गया है। हालाँकि, चार नौसैनिकों, वोग्लिनो रेनाटो (सार्जेंट), एंड्रोनिको मासिमो (प्रथम कॉर्पोरल), फोंटानो एंटोनियो (तीसरा कॉर्पोरल) और कोंटे एलेसेंड्रो (कॉर्पोरल) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, कुछ कठिनाई बनी हुई है।

25. इटली गणराज्य की ओर से हमें सौंपे गए बयान में निर्धारित अपना रुख अपनाते हुए, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इटली गणराज्य इस न्यायालय को आश्वासन देने के लिए सहमत है कि यदि इन 4 नौसैनिकों की उपस्थिति किसी भी न्यायालय द्वारा आवश्यक है या किसी न्यायालय या वैध प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी सम्मन के जवाब में, इटली गणराज्य उचित न्यायालय या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। यह आश्वासन भारत में सक्षम अदालत के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के अधिकार के अधीन है। हमारे विचार में, इटली

गणराज्य द्वारा इन चार नौसैनिकों, अर्थात्, वोग्लिनो रेनैटो (सार्जेंट), एंड्रोनिको मास्सिमो (प्रथम कॉर्पोरल), फोंटानो एंटोनियो (तीसरा कॉर्पोरल) और कोंटे एलेसेंड्रो (कॉर्पोरल) की उपस्थिति को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया है। किसी भी न्यायालय या वैध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित, न्याय के उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा करता है और केरल सरकार के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। यह किसी भी तरह से केरल सरकार के जांच को आगे बढ़ाने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील का निपटान निम्नलिखित आदेश द्वारा करते हैं:-

(1) जैसा कि नीचे बताया गया है, अपीलकर्ताओं द्वारा अनुपालन के अधीन, केरल सरकार और उसके अधिकारी पहले अपीलकर्ता जहाज को अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति देंगे: -

पहले अपीलकर्ता जहाज के मास्टर, पहले अपीलकर्ता जहाज के मालिक के प्रबंध निदेशक और शिपिंग एजेंट के प्रबंध निदेशक, अर्थात्, जेम्स मैकिन्टोश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की संतुष्टि के लिए अपने उपक्रम

प्रस्तुत करेगा कि छह चालक दल के सदस्य, अर्थात्, विटेली अम्बर्टो (मास्टर), नोविल्लो कार्लो (मास्टर एसएन), जेम्स मांडली सैमसन (मुख्य अधिकारी), साहिल गुप्ता (द्वितीय अधिकारी) फुलबरिया (सीमैन) और तिरुमाला राव (साधारण सी मैन), किसी भी अदालत से या जांच अधिकारी या वैध प्राधिकारी द्वारा समन/नोटिस प्राप्त होने पर ऐसे समन/नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर खुद को पेश करेंगे। यदि किसी अदालत या जांच अधिकारी या किसी अन्य वैध प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो, तो ऐसे समन/नोटिस की प्राप्ति से सात सप्ताह के भीतर प्रथम अपीलकर्ता को पेश करें।

दूसरा अपीलकर्ता पहले अपीलकर्ता जहाज के उत्पादन के लिए केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष तीन करोड़ रुपये की राशि का एक बांड निष्पादित करेगा और जब भी किसी द्वारा बुलाया जाएगा, उपरोक्त छह चालक दल के सदस्यों की उपस्थिति अदालत या जांच अधिकारी या कोई अन्य वैध प्राधिकारी के समक्ष सुनिश्चित करेगा।

(2) इटली गणराज्य द्वारा दिया गया आश्वासन कि यदि चार नौसैनिकों, अर्थात् वोग्लिनो रेनाटो (सार्जेंट), एंड्रोनिको मासिमो (प्रथम कॉर्पोरल), फोंटानो एंटोनियो (तीसरा कॉर्पोरल) और कोंटे एलेसेंड्रो

(कॉर्पोरल) की उपस्थिति आवश्यक है किसी भी अदालत या वैध प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा, इटली गणराज्य ऐसी अदालत या वैध प्राधिकारी या जांच अधिकारी के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, इस तरह का आश्वासन, भारत में सक्षम अदालत के समक्ष किसी भी अदालत या जांच अधिकारी या किसी अन्य वैध प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे समन/नोटिस को चुनौती देने के उपरोक्त चार नौसैनिकों के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

27. यह स्पष्ट किया गया है कि नींदकारा तटीय पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 2/2012 की जांच कानून के अनुसार उपरोक्त उपक्रम और बांड के उपरांत भी बंदरगाह और सीमा शुल्क मंजूरी के अधीन पहले अपीलकर्ता जहाज द्वारा यात्रा शुरू करने में बाधा नहीं बनेगी।

28. चार नौसैनिक, अर्थात्, वोग्लिनो रेनैटो (सार्जेंट), एंड्रोनिको मास्सिमो (प्रथम कॉर्पोरल), फोंटानो एंटोनियो (तीसरा कॉर्पोरल) और कोंटे एलेसेंड्रो (कॉर्पोरल), जांच अधिकारी द्वारा पहले से ही जब्त किए गए आलमात के अलावा सभी उपकरणों, हथियारों और गोला-बारूद के साथ जहाज पर रवाना हो सकते हैं।

29. कॉस्ट से सम्बंधित कोई आदेश नहीं।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' और अन्य की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **नीरज भामू (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।